भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1859
उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच

1859. डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री पी. पी. चौधरीः
कैप्टन बृजेश चौटाः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री मनोज तिवारीः
श्री अनूप प्रधान वाल्मीकिः
श्री भोजराज नागः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः
श्री गोडम नागेशः
श्री अभिमन्यु सेठीः
श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः
श्री शंकर लालवानीः
डॉ. विनोद कुमार बिंदः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः
श्री राजीव प्रताप रूडी:
श्री बंटी विवेक साहूः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः
श्री बिभु प्रसाद तराईः
श्री नलिन सोरेनः
श्री काली चरण सिंहः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश विशेषकर छिंदवाड़ा जिला, छत्तीसगढ़ विशेषकर बस्तर क्षेत्र, ओडिशा विशेषकर कंधमाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक विशेषकर दक्षिण कन्नड़ जिला, राजस्थान विशेषकर पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के सारण जिले सहित ग्रामीण भारत में इंटरनेट की पहुंच का मौजूदा स्तर क्या है, जिसे ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की कुल संख्या, ब्रॉडबैंड घनत्व, औसत डेटा खपत और फिक्स्ड और मोबाइल ब्रॉडबैंड के लिए अलग-अलग डेटा के हिसाब से मापा जाता है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले, ओडिशा और वहाँ के कंधमाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश विशेषकर छिंदवाड़ा जिले सहित ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में वर्ष-वार कितनी वृद्धि हुई है और इस संबंध में छत्तीसगढ़ का राज्य-वार रैंकिंग का ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण इंटरनेट की पहुंच के संबंध में राज्यों के बीच कितनी असमानताएं व्याप्त हैं और तत्संबंधी राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना की स्थिति क्या है;

(घ) छत्तीसगढ़ के कौन-कौन से जिले अभी भी कम संपर्क वाले क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं;

(ङ) सार्वभौमिक ग्रामीण संपर्क प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा किन-किन विभिन्न संकेतकों का उपयोग किया जाता है और छिंदवाड़ा जैसे आकांक्षी जिलों में इन संकेतकों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं;

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान कंधमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित ओडिशा में ग्रामीण डिजिटल सम्पर्क कार्यक्रमों पर कितना व्यय किया गया है और वर्तमान वित्त वर्ष के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया है;

(छ) सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कितने ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट पहुंच की सुविधा नहीं है और इन क्षेत्रों में इंटरनेट सम्पर्क कब तक उपलब्ध होने की संभावना है;

(ज) क्या ऑप्टिकल फाइबर केबल की लंबाई में वृद्धि से ब्रॉडबैंड की गति, नेटवर्क विश्वसनीयता और 4जी/5जी की तैयारी में सुधार हुआ है और यदि हां, तो नेटवर्क के निष्पादन के संदर्भ में क्या मापन योग्य परिणाम पाए गए हैं; और

(झ) क्या सरकार ने पश्चिमी घाट क्षेत्रों के लिए कोई विशेष उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं, ग्रामीण ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं (फिक्सड और मोबाइल के लिए अलग-अलग) की कुल संख्या और प्रति वायरलेस उपभोक्ता द्वारा औसत डेटा खपत अनुबंध-1 में संलग्न है।

(ख) और (ग) विगत 3 वर्षों के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में वर्ष-वार वृद्धि और राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्यों के बीच मौजूदा असमानताओं को अनुबंध-II में देखा जा सकता है।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जिलों में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में सेवा से वंचित गांव हैं। डीबीएन (डिजिटल भारत निधि) द्वारा वित्तपोषित विभिन्न चालू परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से दूरस्थ, अल्पसेवित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है।

(ङ) सार्वभौमिक ग्रामीण कनेक्टिविटी प्राप्त करने की दिशा में की गई प्रगति विभिन्न मापदंडों जैसे मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड तक पहुंच के माध्यम से परिलक्षित होती है। ये मापदंड केवल राज्य-वार मापे जाते हैं।

(च) सरकार ने विगत 3 वित्त वर्षों के दौरान ओडिशा के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न डीबीएन स्कीमों के तहत 1814.32 करोड़ रूपए की राशि संवितरित की है, जिसमें कंधमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है। इसके अलावा, वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में ओडिशा सहित देश में डीबीएन परियोजनाओं के लिए 9650 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

(छ) सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 1960 गांवों में से 1895 गांवों में इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं की पहुंच है। कवरेज का विस्तार एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है जो सेवाओं के सेचुरेशन में परिणत होता है।

(ज) सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर केबल की लंबाई में वृद्धि और दूरसंचार सेवाओं में सुधार सहित नेटवर्क अवसंरचना के प्रसार के लिए कई पहल की हैं। देश भर में मापन योग्य सुधारों में मार्च 2022 में मोबाइल ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड 13.67 एमबीपीएस से बढ़कर दिसंबर 2025 में 132 एमबीपीएस (ओकला के ग्लोबल स्पीडटेस्ट इंडेक्स के अनुसार) हो गई, 4जी / 5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की संख्या में 51.33% की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2022 में 16.91 लाख से बढ़कर 31 दिसंबर, 2025 में 25.59 लाख हो गई, और टीएसपी द्वारा सभी क्यूओएस मापदंडों का सामान्य अनुपालन हो रहा है (दिसंबर 2025 के लिए ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार)।

(झ) सरकार ने पश्चिमी घाट क्षेत्रों सहित देश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कई परियोजनाएं आरंभ की हैं। इनमें भारतनेट के माध्यम से मोबाइल कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

अनुबंध-I

"ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच" के संबंध में 11 फरवरी 2026 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1859 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं, ग्रामीण ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं (फिक्सड और मोबाइल के लिए अलग-अलग) की कुल संख्या और प्रति वायरलेस उपभोक्ता द्वारा औसत डेटा खपत।

क्र. सं.	**राज्य / संघ राज्य क्षेत्र**	**इंटरनेट उपभोक्ता (मिलियन में) सितंबर 2025**	**ब्रॉडबैंड उपभोक्ता (मिलियन में) सितंबर 2025**	**फिक्सड ब्रॉडबैंड उपभोक्ता (मिलियन में) सितंबर 2025**	**मोबाइल ब्रॉडबैंड उपभोक्ता (मिलियन में) सितंबर 2025**	**प्रति वायरलेस डेटा उपभोक्ता औसत वायरलेस डेटा का प्रयोग (मिलियन में) नवम्बर 2025**
1	आंध्र प्रदेश	18.28	17.86	0.89	16.97	26,182
2	अरुणाचल प्रदेश	0.73	0.73	0.02	0.71	36,134
3	असम	14.20	14.09	0.16	13.93	29,507
4	बिहार	40.03	39.32	0.50	38.83	30,311
5	छत्तीसगढ	9.39	9.31	0.11	9.20	23,415
6	गोवा	0.66	0.65	0.04	0.62	22,866
7	गुजरात	21.35	21.16	0.43	20.73	33,657
8	हरियाणा	10.31	10.14	0.42	9.72	24,742
9	हिमाचल प्रदेश	4.36	4.33	0.14	4.19	28,897

10	झारखंड	11.74	11.61	0.17	11.44	31,018
11	कर्नाटक	22.32	21.09	0.44	20.65	25,786
12	केरल	17.99	17.46	2.14	15.32	21,880
13	मध्य प्रदेश	21.87	21.61	0.28	21.33	24,713
14	महाराष्ट्र	34.58	34.17	0.47	33.69	27,242
15	मणिपुर	0.83	0.82	0.08	0.75	27,540
16	मेघालय	1.64	1.64	0.02	1.61	25,646
17	मिजोरम	0.49	0.49	0.02	0.46	22,717
18	नागालैंड	0.74	0.73	0.02	0.72	30,325
19	उड़ीसा	17.97	17.82	0.29	17.53	27,410
20	पंजाब	9.96	9.82	0.90	8.92	26,495
21	राजस्थान	26.55	26.22	0.42	25.81	30,020
22	सिक्किम	0.38	0.38	0.01	0.37	35,065
23	तमिलनाडु	19.07	18.72	0.55	18.17	26,994
24	तेलंगाना	13.34	13.11	0.32	12.79	26,394
25	त्रिपुरा	1.30	1.29	0.02	1.27	28,743
26	उत्तर प्रदेश	68.61	67.22	0.94	66.29	27,513
27	उत्तराखंड	4.86	4.77	0.12	4.65	28,052
28	पश्चिम बंगाल	27.33	26.96	0.72	26.24	27,813
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.23	0.19	0.02	0.17	20,246

30	चंडीगढ़	0.04	0.04	0.01	0.03	24,598
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.32	0.32	0.00	0.31	33,864
32	दिल्ली	0.33	0.29	0.01	0.28	16,813
33	जम्मू और कश्मीर	5.13	5.06	0.16	4.90	26,756
34	लद्दाख	0.32	0.32	0.00	0.32	25,062
35	लक्षद्वीप	0.06	0.04	0.00	0.04	13,957
36	पुद्दुचेरी	0.38	0.36	0.02	0.34	25,766
अखिल-भारत		**427.70**	420.15	10.85	409.29	27, 141

अनुबंध-II

"ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच" के संबंध में 11 फरवरी 2026 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1859 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार संख्या (मिलियन में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च 2023	मार्च 2024	मार्च 2025
1	आंध्र प्रदेश	16.79	17.89	17.98
2	अरुणाचल प्रदेश	0.46	0.53	0.54
3	असम	10.98	12.75	13.38
4	बिहार	32.27	37.03	37.57
5	छत्तीसगढ	7.48	8.39	8.55
6	गोवा	0.71	0.83	0.63
7	गुजरात	17.04	18.56	19.18
8	हरियाणा	8.53	9.96	10.11
9	हिमाचल प्रदेश	3.87	4.03	4
10	झारखंड	9.84	10.98	10.94
11	कर्नाटक	19.29	20.79	21.47
12	केरल	15.03	15.88	18.22
13	मध्य प्रदेश	17.88	20.17	21.13
14	महाराष्ट्र	31.64	33.76	32.84
15	मणिपुर	0.91	0.95	0.98
16	मेघालय	1.22	1.32	1.34
17	मिजोरम	0.49	0.53	0.54
18	नागालैंड	0.93	0.98	0.98
19	उड़ीसा	14.79	16.15	17.1
20	पंजाब	9.04	9.81	9.6
21	राजस्थान	22.19	25.75	26.07

22	सिक्किम	0.39	0.31	0.37
23	तमिलनाडु	16.04	17.23	18.01
24	तेलंगाना	12.15	13.1	13.08
25	त्रिपुरा	0.98	1.06	1.07
26	उत्तर प्रदेश	54.16	63.77	65.41
27	उत्तराखंड	4.26	4.9	4.81
28	पश्चिम बंगाल	22.68	25.15	25.61
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.21	0.2	0.23
30	चंडीगढ़	0.04	0.04	0.03
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.25	0.29	0.3
32	दिल्ली	0.77	0.29	0.31
33	जम्मू और कश्मीर	4.21	4.33	4.58
34	लद्दाख	0.16	0.24	0.32
35	लक्षद्वीप	0.05	0.06	0.05
36	पुद्दुचेरी	0.26	0.36	0.36
अखिल-भारत		**357.99**	**398.35**	**407.69**

******